the Government level from time to time.

SHRIMATI GEETA MUKHERJEE: The hon. Minister in reply to my question (a) and (b) which pertain to suspension of Coal Supply to Durgapur Project by Coal India Ltd, for non-payment of dues has come up with a blank answer which is:

(a) No, Sir.

(b) Does not arise.

I believe, this statement came from Coal India Ltd. He did not go into the fact whether there was any suspension of supply to Durgapur Project by Coal India Ltd. As responsible a person as the Minister for Industries in West Bengal Government mentioned in a public statement that DPL had Rs. 4 crores of dues to the Coal India Limited and so the CIL suspended coal supply to D P L. There was a lot of agitation which came in our newspapers also. After all those agitations, the Coal India Limited came out with a concocted reply that it is not due to the coal supply suspension by the CIL but is was because some contractor rates were not tallying with the D P L..

Now, I would like to know whether the hon. Minister before giving me the reply enquired into the statement made by the West Bengal Minister for Industries? If so, whether he verified from him that whether the suspension was done because there was a due of Rs. 4 crores only when the amounts ranging from Rs. 26 crores to Rs. 7 crores are outstanding with 10 other companies or establishments, who are much bigger borrowers from the CIL?

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: Is it CIL or CIA?

SHRIMATI GEETA MUKHERJEE: It is CIL.

SHRI DALBIR SINGH: So far as the reference made by the hon. Member is concerned, I can say that we have not received any such complaint. But we have not suspended any supply to them and I can go by the figures supplied to me by the Department.

MR. SPEAKER: Both are hon. Ministers. Whom should I believe?

SHRIMATI GEETA MUKHERJEE: Well, so far as these two hon. Ministers are concerned, this hon. Member could write to that hon. Minister and make a statement subsequently. That would have been better.

My next question is about the recovery. This is a very interesting statement. Rs. 26 crores, Rs. 23 crores etc., etc., are outstanding with the various companies of CIL and out of the 10 such companies, two are Central Railway and Northern Railway. Now, the reply is that they are writing only to the State Governments. Nobody seems to have written to the Railways or the Central Government departments and the fact remains that the Coal India Limited, is showing all this to deny the house building and other facilities and all that to workers. I would like to know whether the Coal India Limited is really making a serious attempt without any political discrimination to recover the outstanding money and pay the workers so that the production be smoothly enhanced?

SHRI DALBIR SINGH: So far as the question of discrimination is concerned, we, on our side, do not make any discrimination between one defaulter and the other. We rather write to every defaulter who-so-ever-and use the specific measures to recover the amount. The question of discrimination etc., does not arise at all.

Vacancies of Judges in Supreme Court and High Courts.

+

*25. SHRI TRILOK CHAND:
SHRI RAM VILAS PASWAN:

Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to lay a statement stating;

(a) the present position with regard to the vacancies of Judges in the Sup-

reme Court and various High Courts in the country and the number of the sitting Judges as against the sanctioned strength, court-wise; and

(b) the reasons for delay in filling up the remaining vacancies of Supreme Court and High Court Judges?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI GHULAM NABI AZAD): (a) A statement showing the sanctioned strength, actual strength and vacancies of Judges as on 1-2-1983 in the Supreme Court and the High Courts is laid on the Table of the House.

(b). The constitutional provision with regard to the making of appointments of Judges in the Supreme Court and High Courts is a complex one, involving consultation among various authorities. Some proposals for appointments in the High Court have been received from the State authorities and they are engaging the attention of the Government. In several cases proposals are awaited from the States for which they are constantly reminded.

The matter regarding filing up the vacancies of Judges in the Supreme Court is also engaging the attention of the Government.

Statement

as on 1-2-1983

S.No.	High Courts	Sanctioned Strength	Actual Strength	Vacancies
1	Allahabad	60	44	16
2	Andhra Pradesh	26	22	4
3	Bombay	43	36	7
4	Calcutta	39	29	10
5	Delhi	27	21	6
6	Gauhati	9	8	1
7	Gujarat	20	19	1
8	Himachal Pradesh	5	4	1
9	Jammu & Kashmir	7	4	3
10	Karnataka	24	23	1
11	Kerala	18	14	4
12	Madhya Pradesh	29	17	12
13	Madras	25	20	5
14	Orissa	8	6	2
15	Punjab & Haryana	23	22	1
16	Patna	35	32	3
17	Rajasthan	18	12	6
18	Sikkim	2	2	..
		418	335	83
Supreme Court		18	13	5

श्री त्रिलोक चन्द : अध्यक्ष महोदय अभी जो सवाल का जवाब सदन में मंत्री महोदय द्वारा दिया गया, उसको आपने भी सुना है। इसमें कहा गया है कि उच्च न्यायालय में 83 पद और उच्चतम न्यायालय में 5 पद जजों के खाली हैं, लेकिन मंत्री जी ने यह बताने का कष्ट नहीं किया कि ये पद कितने वर्षों से खाली हैं। इन्होंने कहा है कि यह एक बड़ी काम्प्लेक्स समस्या है। हर एक आदमी जानता है कि यह एक ज्वाइण्ट प्रक्रिया है जिस में सभी अथारिटीज से पूछना पड़ता है। लेकिन मेरा प्रश्न तो यह था कि ये पोस्टें कब से खाली हैं—इस का जवाब आपने नहीं दिया है।

जहां तक जजों की खोज का सवाल है—सरकार अपने मन का जज खोजने में लगी रहती है, जब उसके मन का जज मिल जाता है तब एप्वाइन्टमेंट हो जाती है।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : मैं माननीय सदस्य और हाउस को यह बतलाना चाहता हूं कि 1982 में हम ने 59 एडीशनल जजेज को परमानेण्ट किया है, 17 फ्रेश एडीशनल जजेज एप्वाइण्ट किये हैं और 20 परमानेण्ट जजेज एप्वाइण्ट किये हैं। 1983 में 2 एडीशनल जजेज एप्वाइण्ट किये हैं और 4 परमानेण्ट जजेज एप्वाइण्ट किये हैं—इन की संख्या आप देखेंगे, 102 बनती है।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या इन में शेड्यूल्ड कास्ट्स के भी थे ?

श्रीमती प्रमिला दंडवते : इन में महिलायें कितनी हैं ?

श्री जगन्नाथ कौशल : दूसरी बात—जो माननीय सदस्य कहते हैं कि सरकार इस खोज में रहती है कि जब तक सरकार के अपने मतलब के जज न मिलें तब तक सरकार उन को नहीं लगाती है, यह बात माननीय सदस्य बार-बार कहते हैं, बारबार उस का जवाब एक ही है कि यह निराधार बात है कि सरकार ऐसी खोज में रहती है।

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY: What about Baharul Islam?

श्री जगन्नाथ कौशल : सरकार उन जजेज की खोज में रहती है जो सूटेबिल हैं, जो कांस्टीचूशन की फिलासफी में यकीन रखते हैं, जिनका कांस्टीचूशन के प्रति कमिटमेण्ट है, जिन का कांस्टीचूशन में विश्वास है . . . .

श्री रामविलास पासवान : कौनसा कांस्टीचूशन ?

श्री जगन्नाथ कौशल : यह बात कहना कि कन्सलटेशन करने में समय नहीं लगता है, यह गलत बात है। जब तक ये अथारिटीज आपस में एग्रीन करें, हमारी यह कोशिश होती है कि उन को री-कन्साइल करने के बाद बेस्ट आदमी को एप्वाइण्ट करें।

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY: What is the philosophy?

MR. SPEAKER: Only Professor can tell it.

श्री त्रिलोक चन्द्र : ये 102 पोस्टें कब से खाली थीं ? कब से आपने इन को खाली डिक्लेअर किया था आप कहते हैं कि इस वक्त भी हाईकोर्ट में 83 और सुप्रीम कोर्ट में 5 पोस्टें खाली हैं—ये कब से खाली हैं ?

श्री जगन्नाथ कौशल : कुछ पोस्ट 1981 में खाली हुई, कुछ 1982 में खाली हुई। माननीय सदस्य को यह मालूम होना चाहिए कि यह काण्टीन्यूएंस प्रोसेस है, जजेज़ रिटायर होते रहते हैं, अनफ़ार्चुनेटली कुछ जजेज़ की डेथ हो गई, इसलिए ये पोस्टें खाली होती रहती हैं। लेकिन यह कहना कि सरकार इस मामले में सचेत नहीं है, गलत है। आप देखलें हम ने एक साल में कितने एप्वाइण्टमेण्ट्स किये हैं।

श्री रामविलास पासवान : अभी मंत्री जी ने कहा कि अपोज़ीशन की तरफ से बार-बार यह प्रश्न किया जाता है कि आप पोलिटिकली मोटिवेटेड लोगों की चर्चा करते हैं और सरकार बारबार इन्कार करती है, उस को निराधार साबित करती है। मैं यह बात जानना चाहता हूं—एक जज जिस ने एक मुख्य मंत्री के केस में खुल्लमखुल्ला, पक्षपात किया और पक्षपात करने के बाद आप ने अपने टिकट से उसको चुनाव लड़ाने का काम किया...

(व्यवधान)

आचार्य भगवान देव : अध्यक्ष जी, इस से इस मामले का सम्बन्ध क्या है ?

श्री राम विलास पासवान : I amend it.

मुख्य मंत्री के पक्ष में फैसला दिया है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यह तो फैक्ट है।

श्री राम विलास पासवान : मुख्य मंत्री के फ़ेवर में फ़ैसला दिया है, इस में दो राय नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय : न्याय जो होगा, वह किसी के पक्ष में तो होगा ही इस पक्ष में हो या उस पक्ष में।

श्री राम विलास पासवान : जो पक्ष का पात्र होता है, उसी को पक्षपात कहते हैं। उन के पक्ष में फ़ैसला दिया है, इसलिए पक्षपात हुआ है। ..(व्यवधान)..

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अब वज्रपात कर रहे हैं। :

श्री राम विलास पासवान : यह फैक्ट है। सरकार ने क्यों ऐसे आदमी को टिकट दिया, जो आदमी एक दिन पहले ऐसा फ़ैसला देता है और उस को आप अपनी पार्टी में ले लेते हैं।...(व्यवधान)..

आचार्य भगवान देव : अध्यक्ष जी, मुझे इस में आपत्ति है।

श्री राम विलास पासवान : वे पहले भी इन की पार्टी में एम० पी० रह चुके हैं और बाद में जा कर इन की पार्टी में रहे।

अध्यक्ष महोदय : जब आदमी जज हो जाता है, तो उस के बाद वह और कुछ नहीं रहता है।

श्री राम विलास पासवान : जजमेंट देने के लिए उन्हें जज नियुक्त किया गया। ..(व्यवधान).. मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह सरकार की नीति है....

SHRI JAGDISH TYTLER: Who was their candidate for Presidentship? You answer.

SHRI RAM VILAS PASWAN: That was the president of India. That was not the president of Congress—I.

SHRI JAGDISH TYTLER: He also retires. He also will die.

SHRI RAM VILAS PASWAN: President of India is not a party post.

अध्यक्ष महोदय : जज होने के बाद पार्टी पोजीशन खत्म हो जाती है ।

If he is a real judge.

SHRI RAM VILAS PASWAN: Should be.

आचार्य भगवान देव : जनता पार्टी की सरकार में स्पीकर कौन थे, मैं इन से यह जानना चाहता हूं ।

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY: It was also a religious matter. He was worshipping God Jagannath.

MR. SPEAKER: It is a moral principle. If once a judge, he is a judge. He renounces everything. If he is a real judge, he means a judge, he has to dispense justice irrespective of anything, if he be a judge. Is it not? If he once takes the oath of office, I do not think he has anything against anybody.

PROF. MADHU DANDAVATE: Once he becomes a Speaker, he is completely a non-party man.

MR. SPEAKER: I will adhere to that principle as long as I sit here in this House.

श्री राम विलास पासवान : मैं सरकार से एक किलियर-कट क्वेशचन पूछना चाहता हूं ।

श्री एम राम गोपाल रेड्डी : यह जो इन्होंने जज के बारे में कहा है, इसको एक्सपेंज करिये । . . (व्यवधान) . .

श्री राम विलास पासवान : मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि सभी मुख्य न्यायाधीशों की एक कान्फ्रेन्स हुई थी, जिसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश श्री चन्द्र चूड़ ने की थी और जिस में नियुक्तियों आदि के सम्बन्ध में चर्चाएं हुई थीं ? वे चर्चाएं क्या है, यह मैं सरकार से पूछना चाहता हूं ।

आपने हाई कोर्टों के जजों के बारे में बतलाया कि हम विचार कर रहे हैं । मैं जानना चाहता हूं कि हाई कोर्टों के मुख्य न्यायाधीशों ने कितने नाम रिकमेंड किये हैं, कितने नामों पर स्टेट के चीफ़ मिनिस्टर्स ने अनुमति दे दी है, उन का एप्रूवल आप ने किया है या नहीं और कितने आपके पास पेंडिंग हैं । मैं सरकार से यह पुनः पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार ऐसा चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज जो भी नियुक्त हों, वे निष्पक्ष हों और वे आपके लिए कमिटेड न रहें । क्या सरकार इस बात को साफ़ करेगी ?

श्री जगन्नाथ कौशल : मेरी समझ में नहीं आता कि सरकार साफ़ कैसे करे । मैं बार-बार आप को कह रहा हूं कि जजों की नियुक्तियों में हमारा सिर्फ एक कंसिडरेशन है, और वह कंसिडरेशन है,

Integrity. Has faith in the Constitution. He has to uphold the Constitution and the laws.

और यह अपोजिशन एक तरफ इंडीपेंडेंस आफ जुडीशियरी की दुहाई देती है और दूसरी तरफ इस किस्म की बात कर के इंडीपेंडेंस आफ जुडीशियरी पर सब से बड़ा आघात ये करते हैं ।

(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, हमने एक प्रश्न पूछा था कि

क्या हाई कोर्टों के मुख्य न्यायाधीशों की कांफ़ेंस हुई थी जिसकी अध्यक्षता प्रधान न्यायाधीश श्री चन्द्रचूड़ ने की थी ? यदि हां, तो उसमें क्या विचार हुआ ?

श्री जगन्नाथ कौशल : चीफ़ जस्टिसिज को जो कांफ़ेंस हुई थी और उसमें जो विचार हुए थे, उनकी कोई सूची अभी तक हमारे पास चीफ जस्टिस आफ इंडिया ने नहीं भेजी है ।

SHRI SOMNATH CHATTERJEE: This is a matter of great concern. You will appreciate that not only in this House but outside also those who are concerned with the maintenance of the judicial system and process in this country are greatly concerned that so many vacancies are not being filled up for years. Not only vacancies are being caused by death or superannuation but judges are also being induced to retire from the Benches for the purpose of giving party tickets and this is also causing vacancies. I would like to know this. Is it not known long, long before as to when judges are going to retire? Are their ages not known? When the vacancies will be caused, everybody knows, unless the age of a judge is altered from time to time. I want to know why action is not taken well in time to fill up the vecencies as and when they are caused. Would the process start after the vacancies are caused, when everything is known? The Calcutta High Court Chief Justice is retiring on 1st March and till today we do not know who is the next Chief Justice.

AN HON. MEMBER: In Jammu & Kashmir also.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE: There are vacancies of five Judges in the Supreme Court. I want to know, out of these 83 plus 5 vacancies, how many are to be filled up this year. I am giving one year's time. I also want to know whether the proposal of the Government to transfer judges is going to be implemented at the time of apointment of judges, and whether, in respect of Chief Justices, the decision which has been taken to bring them from other High Courts in going to be implemented. while filling up the next vacancies Chief Justices. Why don't you clarify all this so that people could know? Otherwise, there are bound to be comments, there is bound to be suspicion.

श्री जगन्नाथ कौशल : मैं माननीय सदस्य के नोटिस में यह लाना चाहता हूं हमने अक्टूबर, नवम्बर और दिसम्बर के महीनों में 27 वेकेन्सीज भरी हैं ।

SHRI SOMNATH CHATTERJEE: You have given the figures.

श्री जगन्नाथ कौशल : हम वेकेन्सीज भरने के प्रोसेस में लगे हुए हैं। जब स्टेट्स से हमारे पास मुकम्मिल रिकमण्डेशन नहीं आती, और मुझे यह कहना अच्छा नहीं लगता कि आपकी स्टेट रिकमण्डेशन नहीं भेजती, चीफ मिनिस्टर यह कहते हैं कि हम रिकमण्डेशन भेजेंगे ....

SHRI SOMNATH CHATTERJEE: What is the good of sending the recommendations? The names he has objected to, you have appointed those people. So, what is the good of saying all this? This argument of giving proper respect to the Chief Minister's recommendation is absolutely baseless. Why should he give all those explanations? (*Interruptions*)

श्री जगन्नाथ कौशल : मैं हाउस की .....

SHRI SOMNATH CHATTERJEE: They are not giving any respect to the Chief Ministers' or Governments' recommendations or objections. I can cite instances here. Why is he giving those excuses?

श्री जगन्नाथ कौशल : मैं हाउस की इन्फ़ार्मेशन के लिए यह बात कहना चाहता हूं कि एक तरफ हाउस यह कहता है कि चीफ जस्टिस की रिकमण्डेशंस को ज्यादा वेल्यु दो। दूसरी तरफ ये कहते हैं कि चीफ मिनिस्टर की बात को वैल्यू दो। अगर चीफ मिनिस्टर की बात नहीं मानेंगे... (व्यवधान) ....

SHRI SUNIL MAITRA: No, no. You say that the Chief Minister has not sent the recommendations, That is not correct.

श्री जगन्नाथ कौशल : आप में सुनने की शक्ति होनी चाहिए। जब चीफ मिनिस्टर यह कहे कि मेरी बात नहीं मानी गई तो मैं रेकमण्डेशन नहीं भेजूंगा तो चीफ मिनिस्टर अपनी कांस्टीट्यूशनल रेस-पांसिबिलिटी से भागता है। किसी चीफ मिनिस्टर को ..... (व्यवधान) ...

SHRI SOMNATH CHATTERJEE: Let the Governor sent the recommendations.

SHRI JAGAN NATH KAUSHAL: No dialogue. When I am speaking, I crave the indulgence of the hon Members. When they speak, I do not not interrupt. Otherwise, I can also interrupt at every sentence which you speak........(*Interruptions*)

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY: How can you interrupt? We speak sense and you cannot interrupt.

SHRI JAGAN NATH KAUSHAL: Don't ask me to say that most of what you say is not sense.

MR. SPEAKER: He has avoided as a very good lawyer unparliamentary words.

श्री जगन्नाथ कौशल : मैं हाउस को यह बात बताना चाहता हूं कि न चीफ मिनिस्टर को और न चीफ जस्टिस को प्राइम पोजीशन देने के लिए तैयार हैं। कांस्टीट्यूशन में जो पोजीशन दी है हर अथारिटी को कंसल्टेशन करने का अधिकार है और जब कंसल्टेशन हमारे पास आती है तो जो हमको बैस्ट सूटेबल आदमी हमारे खयाल से होगा उसको हम अपायंट करेंगे।

(व्यवधान)

Several hon Members rose

(*Interruptions*)

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY: On a point of order, Sir.

MR. SPEAKER: No point of order during Question Hour. Please sit down.

(*Interruptions*)

SHRI RAM VILAS PASWAN: What is his point of view?

MR. SPEAKER: His point of view has already been explained. Out of the list he will select the most suitable man.

MR. YADAV.

SHRI JAGAN NATH KAUSHAL: Let me complete the answer. According to the latest decision of the Supreme Court, it is the President of India who is to make an appointment after consulting all the constitutional authorities and when I said.

हमारे खयाल से जो होगा, उसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट उसको अपायंट करेगी, प्रेसीडेंट आफ इंडिया उसको अपाइंट करेगा और मैंने यही कहा है।

The final judge of suitability is the Government of India and n obody should be under any doubt that the appointing authority is the President of India

MR. SPEAKER: Mr Yadav.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE: About the transfer of Judges and appointing an outside Chief Justice he has not said anything.

SHRI JAGAN NATH KAUSHAL: I stated earlier also. The main consideration which prevails with the President of India is the suitability of the person for discharging the high duties of that office. With regard to transfer of Judges, etc......

(*Interruptions*)

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY: Independence of judiciary is involved.

SHRI JAGAN NATH KAUSHAL: This is going to be implemented.

MR. SPEAKER: Mr. D. P. Yadav.

SHRI RATANSINH RAJDA: Who is that new member, Sir?

(*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदय : जहां मर्जी बैठो, मैं क्या कर सकता हूं ।

(व्यवधान)

आचार्य भगवान देव : हम यादव जी का सहर्ष स्वागत करते हैं ।

(व्यवधान)

PROF. SATYASADHAN CHAKRABORTY: Mr. Speaker, Sir, what is this?

MR. SPEAKER: Shri D. P. Yadav.

PROF SATYASADHAN CHAKRABORTY: Sir, what is this? This is also yet another case of Aya Ram Gaya Ram.

AN. HON MEMBER: Going back home.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE: From time to time at least they should give us some information.

PROF. SATYASADHAN CHAKRABORTY: This is how Mrs. Gandhi's party is functioning.

MR. SPEAKER: Mr. Yadav.

इस हमाम में मुझे लगता है सारे... चलिए छोड़िए ।

(व्यवधान)

SHRI D. P. YADAV: Mr. Speaker, Sir,....

(*Interruptions*)

SHRI RATANSINH RAJDA: With your permision, Sir, may I suggest one thing for the establishment of healthy practice? The people who defect must forfeit their right to put question. (*Interruptions*) Let us follow this: Let us establish this healthy practice, Sir.

PROF. SATYASADHAN CHAKRABORTY: He should not ask any question now. (*Interruptions*)

SHRI D. P. YADAV: Sir, you will recall that in this very House the previous Law Minister Mr. Shiv Shankar has very categorically assuerd us that in the matter of appointment of the Judges of the Supreme Court and the High Courts the names of those belonging to the backward classes will be duly considered. There is the constitutional provision also. May I ask the hon. Law Minister whether he sticks to the assurance given by the previous Law Minister Mr. Shiv Shankar regarding the appointment of Judges belonging to backward classes and other scheduled castes and scheduled tribes?

श्री जगन्नाथ कौशल : हाउस के सामने श्री शिवशंकर जीने जो स्टेटमेंट दिया है, मैं उस स्टेटमेंट को ओन करता हूं । लेकिन, आपको मालूम होना चाहिए कि कांस्टीट्यूशन में शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राईब्स के लिए हाईकोर्ट जजेज और सुप्रीम कोर्ट जजेज के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : शिवशंकर जी ने क्या कहा था ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या कर रहे हैं आप ? आप जवाद देंगे क्या ? उनको जवाब देने दीजिए ।

श्री जगन्नाथ कौशल : श्री शिवशंकर ने यह कहा था कि हमने सब स्टेट्स को लिखा है कि जहां भी शैड्यूल्ड कास्ट्स, बेकवर्ड क्लासेज़, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के सूटेबिल कडीडेट्स अवेलएबिल हों वहां उनको प्रीफरेंस देनी चाहिए ।

श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी : और महिलाओं के लिए, सर ?

SHRI N. K. SHEJWALKAR: May I know from the hon. Minister if he has looked into the list which he has given along with his written reply? It has been mentioned there that in Allahabad the vacancies are 16, in Calcutta there are 10 vacancies and in Madhya Pradesh there are 12 vacancies out of 29. In Rajasthan also, there are 6 vacancies out of 18. May I just know whether these vacanices are lying vacant for a long time? It is not that some vacancies have occurred now and some have been filled in between. In Madhya Pradesh, out of 29 vacancies, 12 are lying vacant, that is, 40 per cent of the seats are vacant even today. How can you expect quick disposal of the cases under such circumstances? My information is that of course, the Ministry there is that of the Congress-I. But even then the Chief Minister and the Chief Justice are not in agreement for a common list and that is why this has been pending for a long. Is it a fact or not? Can you give an assurance to the House as to when these large number of vacancies will be filled?

SHRI JAGAN NATH KAUSHAL: For the information of the House, I may mention that 39 names have come to us from various States and Allahabad and Madhya Pradesh have also sent some names and they are under active consideration and we will make every effort to make appointments as soon as possible.

श्री जगपाल सिंह : कब तक कंसीडरेशन करेंगे, 3 साल हो गये हैं ।

Fire in Malabar Hill (Bombay) Telephone Exchange.

*26. DR. VASANT KUMAR PANDIT: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether the new Malabar Hill Telephone Exchange at Bombay was totally destroyed by a devastating fire on 30 December, 1982;

(b) if so, what is the estimated total loss to the imported sophisticated automatic equipment, loss of revenue and loss to the property suffered on account of fire;

(c) what is the estimated cost of replacement at this Exchange;

(d) whether any probe/investigation was done as to the cause of fire; if so, by whom and what are the main points made out in the Report;

(e) whether the Japanese supplier from Hitachi group visited the site of fire and whether they have written to Government conveying their finding; if so, what is their conclusion; and

(f) whether Government suspect any sabotage in this fire; if so, the action taken?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI VIJAY N. PATIL): (a) No, Sir.

(b) (i) A Committee has been appointed to estimate the loss suffered by the telephone exchanges situated in the Malabar Hill Telephone building. The report of the Committee is expected shortly.